रक्षा औद्योगिक गलियारे में आएगा 3.5 हजार करोड़ का निवेश

- झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट व लखनऊ निवेशकों की पसंद
- निवेशकों को एक हजार एकड़ भूमि आवंटन की तैयारी शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : रक्षा औद्योगिक गलियारे में जल्द ही 3.5 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके लिए निवेशकों को एक हजार एकड़ भूमि आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और लखनऊ नोड निवेशकों की पसंद बन रहे हैं। झांसी में गुडलक एस्ट्रा कंपनी 247 एकड़ भूमि पर एक हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। साथ ही रेडवुड ह्यूजेस 247 एकड़ भूमि पर 700 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं सिटाडेल और गुरुत्वा जैसी कंपनियों ने भी रक्षा व उससे संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया है।

अलीगढ़ फेज-2 नोड में स्पेसकेम, मराल और जी-1 आफशोर जैसी कंपनियों द्वारा केमिकल और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा 209.95 एकड़ भूमि पर 672 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। आइजी ड्रोन्स ने ड्रोन टेक्नोलाजी सेक्टर में 100 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं लखनऊ स्थित डिफेंस नोड में भी नेक्सा मुंबई, इंद्रप्रस्थ और प्रोमोटेक जैसी कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं।

स्टार्टअप क्रांति के इंजन बन रहे सेंटर आफ एक्सीलेंसः स्टार्टअप इंडिया के दस साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियों का खाका रखते हुए कहा है कि सात सेंटर आफ एक्सीलेंस प्रदेश को इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के इंजन बन गए हैं। इन सात सेंटरों में उद्यमियों को लैब सुविधाएं, उत्पादों के परीक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और उद्योग जगत से नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर स्टार्टअप इंडिया को सफल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। सरकार ने थीम आधारित सेंटर आफ एक्सीलेंस को स्वीकृति दी है। ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाकचेन, मेडिटेक, टेलिकाम, ड्रोन, एडिटिव, मैन्युफैक्चरिंग और आटोमोटिव टेक्नोलाजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

कारोबार में सुगमता के लिए सुधारों का अगला चरण शुरू होगा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः कारोबार में सुगमता (ईज आफ डुइंग बिजनेस) को लेकर उत्तर प्रदेश में सुधारों का अगल चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में भूमि, भवन व निर्माण, बिजली, श्रम, अग्निशमन, पर्यावरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों में सुधार किया जाएगा।

इसे लेकर भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लखनऊ का दौरा किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन ने मुख्य सचिव एसपी गोयल के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के दूसरे चरण में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नियमों में सुधार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार, डी-रेगुलेशन 1.0 कम्प्लायंस रिडक्शन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में प्रमुख औद्योगिक संगठनों के साथ संवाद किया।

MAGZTER @sirius

Clipped from - Dainik Jagran Lucknow - January 17, 2026

Read it digitally on the Magzter app